खबर संक्षेप

दो प्रकरण में तीन गौवंश तस्कर गिरफ्तार, 6 गौवंश कराए मुक्त

खरगोन। सनावद थानाक्षेत्र में हो रहे गौवंश तस्करी का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो प्रकरण दर्ज किए है। इस मामले में तीन गौ-तस्करों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 6 गौवंश मुक्त कराए गए है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे खरगोन रोड़ पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 10जी 2427 को रोका गया। वाहन में दशरिया निवासी भागरिया फल्या सिरवेल भगवानपुरा और नासरिया निवासी मोटयारी फल्या सिरवैल सवार थे। तलाशी लेने पर वाहन में 3 गौवंश क्रुरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे थे। गौवंश परिवहन संबंधित दस्तावेज नही मिलने पर दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार तरह 4 मई को ढकलगांव में निर्माणाधीन ब्रिज के पास वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 46जी 1552 को रोका गया। वाहन चालक ने अपना नाम पप्पा निवासी सिरवेल भगवानपुरा बताया। वाहन से 3 गौवंश को मुक्त कराया गया है। दोनो प्रकरण में 6 गौवंश मुक्त कराए गए।

किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस की बैठक आज

दतिया। मध्यप्रदेश में किसानों पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में प्रस्तावित नेशनल हाईवे चक्का जाम की रणनीति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दतिया एवं शहर ब्लॉक की संयुक्त बैठक आज 6 मई, बुधवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। जिला कांग्रेस संगठन महासचिव नरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि यह बैठक वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध के निज निवास पर होगी। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी दतिया के प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में रामलखन दंडोतिया शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा करेंगे। बैठक में दतिया विधानसभा प्रभारी दशरथ सिंह गुर्जर, सेवढ़ा विधानसभा प्रभारी योगेंद्र तोमर और भांडेर विधानसभा प्रभारी जसवंत बघेल की विशेष उपस्थिति रहेगी। बैठक में पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील की गई है। रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में अव्यवस्था, किसान परेशान

रायसेन। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू नहीं हैं, जिससे किसानों को बार-बार परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में आ रही है। कई किसानों को समय पर स्लॉट नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वे अपनी उपज लेकर कई दिनों तक केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा तुलाई प्रक्रिया भी बेहद धीमी है।

एसपी का एक्शन,मृगवास में बुजुर्ग दंपति के घर डकैती डालने वाले गिरफ्तार

आरोपियों से नकदी और जेवर के साथ हथियार भी बरामद

पीपुल्स प्रवक्ता गुना।

जिले के मृगवास इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दंपत्ति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीन आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। बता दें कि मृगवास इलाके के बकान्या गांव में रहने वाले वैंकट दास बैरागी खेती किसानी करते हैं। वह अपनी पत्नी मांगी बाई के साथ रहते हैं। 13 अप्रैल की दरमियानी रात एक से डेढ़ बजे के बीच अज्ञात नकाबपोश बदमाश उनके घर में घुस आए। उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया। बदमाशों ने दोनों से जमकर मारपीट की।

महिला को भी मुंह पर थप्पड़ और घूसे मारे गए। बदमाश इस दौरान एक लाख नगदी और सोने चांदी के गहने ले गए। वह बाहर खड़ी कार की चाबी भी ले गए। कुछ दिन पहले बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा रोड स्थित कृषि भूमि प्लाट का विक्रय किया था। प्लाट से दंपत्ति को लगभग 6 लाख मिले थे। नकाबपोश बदमाशों द्वारा बुजुर्ग दंपति से प्लाट की राशि के बारे में बार-बार पूछताछ की गई। बदमाश पूछते रहे कि प्लॉट बेचने से मिले पैसे कहां हैं। हालांकि, दंपत्ति ने नहीं बताया। दंपत्ति ने कहा कि

केवल एक लाख नगदी उनके पास हैं। इस पर भी नकाबपोश बदमाशों को विश्वास नहीं हुआ तो दंपति के मोबाइल में रकम का मैसेज चेक किया गया। दंपति के घर के बाहर एक कार खड़ी थी, उसकी चाबी भी नकाबपोश बदमाश ले आए थे। नकाबपोश बदमाश बाहर का गेट खोलकर और बाहर का गेट में वापस ताला लगाकर फरार हो गए। दंपत्ति ने जैसे तैसे अपने हाथ और मुंह को खोला। रात को छत पर जाकर जोर-जोर से आवाज लगाई, जिसके बाद ग्रामीण एकत्रित हुए। अगले दिन खुद एसपी हितिका वासल मौके पर पहुंची थीं और दंपत्ति से मुलाकात की थी। मृगवास पुलिस ने बताया कि एसपी हितिका वासल ने जल्द इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए घटना स्थल और आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। आसपास के क्षेत्रों के लगभग 100 लोगो से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस ने घटना से पहले के पांच दिनों में घटना स्थल के आसपास उपयोग हुए करीब 10 हजार मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया(

जिनमें एक संदिग्ध नंबर चिन्हित हुआ। इसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा उस मोबाईल नंबर धारक रामधन पुत्र हीरालाल कंजर उम्र 26 साल निवासी चिंता का डेरा ग्राम बिरयाई थाना कुम्भराज को हिरासत में लिया। पुलिस टीम द्वारा संदेही रामधन कंजर से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी मनोहर कंजर सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना करना स्वीकार किया। उसने बताया कि घटना के दो दिन पहले वह लोग शिकार करने के लिए ग्राम बकान्या तरफ गए हुए थे। इस दौरान गांव के बाहर रोड़ पर मकान बना हुआ दिखा था।

सीएमएचओ कुर्सी पर संग्राम

कोर्ट केस के चलते रायसेन में बार-बार बदल रहा स्वास्थ्य विभाग का मुखिया, व्यवस्था चरमराई

अरविंद ताम्रकार
पीपल्स प्रवक्ता रायसेन।

मध्यप्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृह जिले रायसेन में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों गंभीर प्रशासनिक अस्थिरता से जूझ रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (छ्स्व्ह) पद को लेकर चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब खुले टकराव का रूप ले चुकी है, जिससे जिले की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण छ्स्व्ह पद पर बार-बार बदलाव हो रहा है। कभी डॉ. दिनेश खत्री पदभार संभालते नजर आते हैं तो कभी एच.एन. मंड्रे कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। इस उठापटक ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों अधिकारियों के बीच अधिकार और नियंत्रण को लेकर चल रही खींचतान के चलते विभाग दो गुटों में बंट गया है। कर्मचारी भी स्पष्ट नेतृत्व के अभाव में दुविधा में काम कर रहे हैं। नतीजतन, कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबित पड़ी हैं और शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां बनी हुई हैं, ऐसे में इस प्रशासनिक अस्थिरता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है, वहीं जनहित से जुड़े कई निर्णय टलते जा रहे हैं।

स्थानीय जन प्रतिनिधियों और नागरिकों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में इस तरह की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि शासन जल्द हस्तक्षेप कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाले। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि मामला उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक रायसेन का स्वास्थ्य विभाग इस खींचतान का शिकार बना रहेगा और आम जनता इसकी कीमत चुकाती रहेगी।

शहर में अवैध मैरिज गार्डनः कर चोरी, बिजली चोरी और बाल श्रम का खुला खेल, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

पीपुल्स प्रवक्ता गोहद।

शहर के विकास पर ग्रहण लगाते मैरिज गार्डन, नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर सरकारी राजस्व को भारी चूना लगा रहे हैं। बिना अनुमति, बिना लाइसेंस के चल रहे ये अवैध संचालन अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। शहर में शादी-समारोहों के नाम पर संचालित हो रहे मैरिज गार्डन अब प्रशासन और कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शहर के अनेक मैरिज गार्डन बिना किसी वैध अनुमति और लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं। यह अवैध संचालन न केवल स्थानीय निकाय, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण और बिजली विभाग जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

मैरिज गार्डन के संचालन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य है। इनमें स्थानीय निकाय से लेकर अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बिजली विभाग तक शामिल हैं। परंतु, शहर में कई गार्डन इन सभी नियमों को ताक पर रखकर संचालित

हो रहे हैं। इन संचालकों के पास न तो नगर निकाय की अनुमति है, न ही फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र। प्रदूषण और ध्वनि नियमों की भी खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इन गार्डनों में पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था भी शून्य है, जिससे जनता को असुविधा के साथ-साथ जान का खतरा भी बना रहता है। जानकारी के अनुसार, कई मैरिज गार्डन संचालक विवाह कार्यक्रमों की वास्तविक बुकिंग को छिपाकर सरकारी करों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।

जीएसटी और अन्य स्थानीय करों का भुगतान न करके, और केवल नकद लेन-देन के माध्यम से, ये संचालक कर चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस गोरखधंधे से सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है, जो अंततः विकास कार्यों पर ही असर डालता है।

जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का हुआ निराकरण

पीपुल्स प्रवक्ता रायसेन।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आमजन की समस्याओं की सुनवाई की गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अल्का सिंह ने नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही कई प्रकरणों का निराकरण किया। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली तथा अन्य शासकीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें एवं आवेदन प्रस्तुत किए। विभागों के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई कर समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभाग से संबंधित समस्याओं पर आवेदकों से चर्चा कर समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की। जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास लगातार जारी हैं।

मकान सूचीकरण में रायसेन ने फिर किया कमाल

प्रदेश में सर्वाधिक एचएलबी पूर्ण कर रायसेन जिला बना अग्रणी

पीपुल्स प्रवक्ता रायसेन।

जनगणना-2027 के अंतर्गत संचालित हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) में रायसेन जिले ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रभावी कार्यप्रणाली, सुदृढ़ मॉनिटरिंग और व्यापक जनसहभागिता के दम पर जिले ने मकान सूचीकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 2,794 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLBs) में से 429 HLBs का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो पूरे मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है।

04 मई 2026 तक के पोर्टल आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 1,270 HLBs पूर्ण हुई हैं, जिनमें से अकेले रायसेन जिले का योगदान 429 यानी 33.78 प्रतिशत है, जो जिले की सक्रियता और बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। जिले में मकान सूचीकरण के साथ-साथ जनगणना कार्य भी तेज़ी से जारी है। अब तक 1,93,735 जनगणना मकानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें 1,60,280 परिवारों का डेटा संकलित किया गया है। इसके अलावा 7,25,310 लोगों की जनसंख्या का विवरण दर्ज किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि जिले में स्वगणना (Self Enumeration) को भी व्यापक बढ़ावा मिला है। अब तक 21,483 सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट कर उनका सफल उपयोग किया जा चुका है, जिससे आम नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है। जिले में अब केवल 31 HLBs का कार्य शेष है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते रायसेन ने न केवल स्वगणना में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि अब मकान सूचीकरण (Census Houses) में भी शीर्ष पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। यह उपलब्धि जिले के प्रगणकों, पर्यवेक्षकों, चार्ज अधिकारियों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिसने रायसेन को प्रदेश में एक मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।

कलेक्टर बोले- जनसमस्याओं का निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 192 आवेदनों के निराकरण के निर्देश, जरूरतमंदों को मिली आर्थिक सहायता

पीपुल्स प्रवक्ता गुना।

जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन ने तत्परता दिखाई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने विभिन्न आवेदनों पर सीधे आवेदकों से चर्चा कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनसुनवाई में सीमांकन, बिजली, पेंशन, नगरपालिका, स्वास्थ्य एवं नामांतरण से जुड़े कुल 192 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश मौके पर ही दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई के दौरान मानवता का संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला। उकावदखुर्द निवासी कालूराम अहिरवार ने जूता व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सहायता की मांग की, वहीं श्रीमती गायत्री धाकड़ ने अपने पति के इलाज हेतु आर्थिक सहयोग का आवेदन दिया। कलेक्टर कन्याल ने दोनों मामलों में

सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए रेडक्रॉस के माध्यम से 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। सहायता प्राप्त कर आवेदकों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, साथ ही नेत्र परीक्षण एवं एचआईवी जांच जैसी सेवाएं भी दी गईं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को आधार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, संयुक्त कलेक्टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

दतिया कांग्रेस को बड़ा झटकाः गहोई समाज के वरिष्ठ नेता साथियों सहित भाजपा में शामिल

पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में दिलाई सदस्यता

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

जिले की राजनीति में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब गहोई समाज के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में

वरिष्ठ नेता मोहन सुहाने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिजारिया, पप्पू सिजारिया और चंदू साहू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अतुल भूरे चौधरी ने पुष्पमाला और पार्टी पट्टिका पहनाकर सभी नए सदस्यों का स्वागत किया।

कांग्रेस पर लगाए आरोपत्न पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिजारिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गहोई समाज की उपेक्षा की है। समाज के युवाओं और वरिष्ठों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हमेशा समाज को सम्मान दिया और विभिन्न पदों पर अवसर देकर उनका मान बढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि दतिया में कांग्रेस अब कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित रह गई है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूदः इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें जिला मंत्री अतुल भूरे चौधरी, विपिन गोस्वामी, धीरू दांगी, बृजेश यादव, प्रशांत ढेंगुला, योगेश सक्सैना, राजू निचरेले, भानु ठाकुर, पवन पहारिया, बल्लन गुप्ता, आकाश भार्गव और सुमित भार्गव प्रमुख रूप से शामिल रहे।

न्यू राधावल्लभ में बार-बार हो रही चोरियां

व्यापारियों ने एसपी से की चोरों को पकड़ने की मांग

पीपुल्स प्रवक्ता खरगोन।

शहर के राधावल्लभ मार्केट में पिछले तीन माह से लगभग हर वीकेंड पर चोरियां हो रही है। शनिवार-रविवार या रविवार- सोमवार की दरमियानी रात चार से पांच दुकानों के ताले तोड़े जाने के मामले सामने आ रहे है। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद होने के बाद भी चोरों की गिरफ्तारी नही होने या चोरियां नही थमने से व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। मंगलवार को बड़ी संख्या में दुकानदार एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां एसपी के नाम आवेदन देकर चोरों को जल्द गिरफ्तार कर मार्केट को भयमुक्त करने की मांग की है। दुकानदार अमित महाजन एवं संजय गुप्ता ने बताया बार-बार हो रही चोरियों को देखते हुए दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए है। इन कैमरों में कई चोरियां कैद हो चुकी है, फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी के फुटेज हासिल किए, लेकिन इसके उपरांत भी न तो घटना का खुलासा नहीं हुआ न ही चोरियां रुकी। इससे दुकानदारों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हर शनिवार- रविवार यह डर सताता है कि चोर रात में कही वारदात को अंजाम न दे दे।

सालो बाद सनावद रोड़ नाले से हटा अतिक्रमण विरोध के बीच शुरु हुआ सफाई अभियान

पीपुल्स प्रवक्ता खरगोन।

प्रशासनिक एवं नगर पालिका अफसरों की सख्ती के बीच सनावद रोड़ स्थित नाले को अतिक्रमण मुक्त कर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान विरोध के स्वर भी मुखर हुए, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के बीच कार्रवाई बदस्तूर जारी रही।

मंगलवार सुबह 10 बजे एसडीएम वीरेंद्र कटारे, नगर पालिका सीएमओ कमला कौल के नेतृत्व में जिला अस्पताल के सामने स्थित नाले पर किए गए अतिक्रमण हो हटाने की कार्रवाई शुरु की। इस दौरान नाले पर टीन- टप्पर हटाकर नाले पर बनी स्लैब जेसीबी मशीन से तोड़ी गई। इसके बाद नाले में जमी गाद निकालने का काम शुरु किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सरस्वती कॉलोनी के गेट पर लगी दुकान हटाते समय विरोध के स्वर भी मुखर हुए। दुकानदार ने निजी अस्पताल के टीनशेड को हटाने की मांग की। जिससे अधिकारियों से कहासूनी भी हुई। एसडीएम ने निजी अस्पताल संचालक से चर्चा कर अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिसके बाद मामला शांत हुआ। एसडीएम ने बताया नाला पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है, जहां नालों के ऊपर पक्का फर्श, दीवार या सीढ़ियां बनाकर अतिक्रमण किया गया है, उसे सख्ती से हटाया जाएगा।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम से बदली जिंदगीः

बैशाखी मिलने से आत्मनिर्भर बने बाल किशन पाल

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

केंद्र एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 का सकारात्मक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। जनपद पंचायत दतिया के ग्राम डोगरपुर निवासी दिव्यांगजन बाल किशन पाल के जीवन में इसका उल्लेखनीय उदाहरण देखने को मिला है। लंबे समय से दिव्यांगता के कारण बाल किशन पाल को दैनिक कार्यों—जैसे चलना-फिरना, घरेलू कामकाज करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना—में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे सहायक उपकरण की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया था। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला दतिया से संपर्क किया। विभाग ने उनके आवेदन को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई की और आवश्यक परीक्षण के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें निःशुल्क बैशाखी उपलब्ध कराई।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदमः बैशाखी मिलने के बाद बाल किशन पाल के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब वे अपने दैनिक कार्य स्वयं करने में सक्षम हो गए हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। बाल किशन पाल ने इस सहयोग के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए ÷नई जिंदगी की शुरुआत÷ जैसी है।

दिव्यांगजनों के लिए जारी हैं विशेष अभियानःजिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण के साथ विभिन्न योजनाओं का

लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान दिव्य सम्मान भी संचालित किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार, सम्मानजनक जीवन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।